



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2015/ज्येष्ठ 14, 1937

No. 208]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2015/JYAISTHA 14, 1937

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 2 जून, 2015

सं.टीएमपी/46/2014—पीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम (1963 का 38) की धारा 48 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) से प्राप्त, लाइसेंसधारियों द्वारा पारादीप पोर्ट घाट पर उपलब्ध करायी गई ट्रांससिपर संपत्तियों के प्रयोग द्वारा कार्गो प्रहस्तन के लिए शुल्क निर्धारण प्रस्ताव को, निम्नलिखित आदेशानुसार निपटाता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

केस संख्या टीएमपी/46/2014—पीपीटी

पारादीप पत्तन न्यास

आवेदक

कोरम

- | | | |
|------|----------------------------|---------------------|
| (i) | श्री टी एस वालासुब्रहमण्यन | सदस्य (वित्त) |
| (ii) | श्री सी वी सिंह | सदस्य (अर्थशास्त्र) |

आदेश

(मई 2015 के 15वें दिन पारित)

यह मामला पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से सम्बंधित है, जो पारादीप पत्तन घाट पर लाइसेंसधारियों द्वारा प्रयोग के लिए उपलब्ध करायी गई ट्रांससिपर संपत्तियों के प्रयोग द्वारा कार्गो प्रहस्तन प्रभार निर्धारित करने से सम्बंधित है।

2.1. पीपीटी ने अपने दिनांक, 11 सितंबर, 2014 को प्रस्तुत पत्र द्वारा, पारादीप पोर्ट घाट पर लाइसेंसधारियों द्वारा प्रयोग के लिए उपलब्ध करायी गई ट्रांससिपर संपत्तियों के प्रयोग द्वारा कार्गो प्रहस्तन प्रभार को निर्धारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव को प्रशुल्क केस की तरह पंजीकृत किया था और निर्धारित कार्य प्रणाली (विचार-विमर्श) सामान्य सलाह प्रक्रिया/प्रक्रम को अपनाया गया है। प्रस्ताव की संवीक्षा की गयी और सहायक सूचना एवं स्पष्टीकरण पीपीटी से हमारे पत्र दिनांक 10 दिसंबर 2014 द्वारा मांगे गये। सलाह कार्य प्रणाली के रूप में इस मामले में संयुक्त सुनवाई 15 दिसंबर, 2014 को पीपीटी परिसर में आयोजित की गयी।

2.2. बहस के दौरान संयुक्त सुनवाई में यह निष्कर्ष निकला कि पीपीटी परिसम्पतियों के प्रभार के संदर्भ में अपने, प्रस्ताव को और संशोधित करे जिसमें क्रिया कलाप को पूर्ण करने हेतु संपत्तियों का स्थापन, ट्रांससिपर की लागत के बारे में विचार करे। पीपीटी निष्पादन से जुड़े टैरिफ के प्रस्ताव की जांच करने के लिए भी राजी हो गया था। इस संदर्भ में पीपीटी शेरधारकों से सलाह मशवरा करके अपने प्रस्ताव की समीक्षा करने के लिए सहमत हो गया था। तदनुसार, पीपीटी के निवेदन पर दो हफ्तों का समय समीक्षा के लिए और संशोधित प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए दिया गया। उपरोक्त स्थिति पीपीटी को हमारे पत्र द्वारा दिनांक 19 दिसंबर, 2014 द्वारा प्रेषित की गयी।

2.3. इसके जवाब में पीपीटी ने ई मेल दिनांक 26 दिसंबर, 2014 द्वारा 15 दिन में अपना संशोधित प्रस्ताव पेश करने का अनुरोध किया, क्योंकि इसे शेरधारकों से विचार-विमर्श करना था। पीपीटी द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया और पीपीटी को अपने संशोधित प्रस्ताव को दर्ज करने के लिए 12 जनवरी, 2015 तक का समय दिया गया। उक्त सूचना/स्थिति पीपीटी को हमारे पत्र द्वारा दिनांक 30 दिसंबर, 2014 को प्रेषित की गयी।

2.4. इसके पश्चात् पीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 20 जनवरी, 2015 के द्वारा इस विषय को स्थगित करने का अनुरोध इस आधार पर किया, कि जब तक अनुज्ञप्ति के चुनाव और प्रशुल्क दरों के निर्धारण का सिद्धांत रूप में अनुमोदन न हो जाए इस विषय पर आगे चर्चा न हो।

2.5. बाद में, जब हमने पीपीटी से नहीं सुना तब हमने अपने पत्र दिनांक 04 मार्च, 2015 द्वारा पीपीटी को अनुरोध किया कि संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की वर्तमान स्थिति सूचित करें। पीपीटी से यह भी अनुरोध किया कि संशोधित प्रस्ताव को प्रेषित करने की दिनांक सूचित करें।

3. इस संदर्भ में पीपीटी ने अपने दिनांक 21 मार्च, 2015 के द्वारा निम्नलिखित परिकल्पना प्रस्तुत की थी:

- (i) एक विशेष वर्थ वेटी पोत की वर्थिंग, प्रस्तावित ट्रांससिपर परिसम्पति द्वारा लाइटरैज आप्रेशन, के लिए आवश्यक है। जिसके बिना प्रस्ताव आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकता।
- (ii) चूंकि पीपीटी पर कोई वर्थ खाली नहीं है तथा वर्तमान में सभी बर्थों का अधिभोग 90 प्रतिशत से अधिक है, पोर्ट घाट पर लाइटरैज आप्रेशन का प्रस्ताव कुछ समय के लिए स्थगित रखा गया है।
- (iii) इसलिए पारादीप पोर्ट का प्रस्ताव, घाट पर लाइसेंसधारीयों द्वारा प्रयोग के लिए उपलब्ध करायी गई ट्रांससिपर संपत्तियों के प्रयोग द्वारा कार्गो प्रहस्तन के प्रभार को निर्धारित करने को, नहीं लिया गया है।

4. पीपीटी द्वारा प्रदर्शित की गई कठिनाइयों, प्रस्ताव को जारी जारी रखने के इस संदर्भ में, मामला बंद व वापिस ले लिया गया। संशोधित प्रस्ताव जब पीपीटी द्वारा भरे जाएंगे नया मानकर जारी रखा जाएगा।

5. परिणामतः ऊपर दिए गए कारणों से इस प्राधिकरण ने वापिस ले लिया गया मानकर, इस केस को बंद करने का निर्णय लिया है।

टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असा./143/2015(99)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd June, 2015

No. TAMP/46/2014-PPT.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal of the Paradip Port Trust (PPT) for fixation of cargo handling charge for use of transhipper assets provided by licensee at Paradip Port Anchorage, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/46/2014 – PPT

The Paradip Port Trust

Applicant

QUORUM

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 15th day of May 2015)

This case relates to a proposal received from the Paradip Port Trust (PPT) for fixation of cargo handling charge for use of transhipper assets provided by licensee at Paradip Port Anchorage.

2.1. The PPT vide its letter dated 11 September, 2014 has submitted its proposal for fixation of cargo handling charge for use of transhipper assets provided by licensee at Paradip Port Anchorage. The proposal was registered as a tariff case and processed by following the usual consultation procedure prescribed. The proposal was scrutinized and additional information and clarification were sought from PPT vide our letter dated 10 December, 2014. As a part of consultation procedure, a joint hearing in this case in reference was held on 15 December, 2014 at the PPT premises.

2.2. During the discussion that took place during the joint hearing, it emerged that the PPT may have to further fine tune its proposal with regard to the type of assets envisaged to be deployed to carry out the operations and the cost of the transhipper. The PPT had also agreed to examine and propose performance linked tariff. In this context, the PPT agreed to review its proposal in consultation with stakeholders. Accordingly, at the request of PPT, the PPT was given two weeks' time to review and furnish its revised proposal. The above position was communicated to the PPT vide our letter dated 19 December, 2014.

2.3. In response, the PPT vide its email dated 26 December, 2014 made a request to allow them 15 day's time to submit their revised proposal, as it required consultation with Stakeholders. The request made by PPT was acceded to and the PPT was given time upto 12 January, 2015 to file its revised proposal. This position was communicated to the PPT vide our letter dated 30 December, 2014.

2.4. Thereafter, the PPT vide its letter dated 20 January, 2015 requested to keep its subject proposal in abeyance till its further communication on the ground that the revised modalities for selection of licensee and fixation of tariff has not yet been approved in-principle.

2.5. When we did not hear from PPT subsequently, we have vide our letter dated 04 March, 2015 requested the PPT to communicate the present status of formulation of its revised proposal. The PPT was also requested to indicate a date by which it envisaged the submission of its revised proposal.

3. In this regard, the PPT vide its letter dated 21 March, 2015 has made the following submissions:

- (i) An exclusive berth is required for berthing of daughter vessels in the proposed lighterage operation through transhipper assets without which the proposition may not be economically viable.
- (ii) Since PPT has no spare berth and since occupancy of all berths is more than 90% at present, the proposal for lighterage operation in Port anchorage has been kept on hold for time being.
- (iii) Therefore, the PPT proposal for fixation of cargo handling charges for use of transhipper assets provided by the licensee at Paradip Port Anchorage may not be taken up.

4. In view of the difficulties expressed by the PPT to go ahead with the proposal, the case in reference is closed as withdrawn. The revised proposal will be processed afresh, when filed by the PPT.

5. In the result, and for the reasons given above this Authority decides to close this case as withdrawn.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.III/4/ Exty./143/2015(99)]